DELHI SARKARI RATION DEALER'S SANGH - DELHI

Office : Shop No. 2 & 3, C-4, DDA Market, First Floor, Lawrance Road, Keshavpuram, Delhi-110035
E-mail : dsrdsdelhi@gmail.com Website : www.dsrdsdelhi.com

HCP-3 SRS1

DSRDS

2017 671639

Ref. : DSRDS-DELHI/2017/NO. 212-215 *Date :* 31-08-17

SHIV KUMAR GARG *President* 9212567435

JAGDISH PRASHAD *Sr. Vice President* 9810406015

KUNJ BIHARI BANSAL *Vice-president* 9810630323

SHYAM SUNDAR *Vice President* 9911178848

SUNIL SHARMA *Vice President* 9310023180

MANOJ SHARMA *Vice President* 9582203929

HARI KRISHAN (LILU) *Vice-President* 9212442834

SITA RAM *Gen. Secretary* 9312238830

RAJNEESH SHARMA *Secretary* 9818569678

SAURABH GUPTA *Secretary* 9810943745

MATLOOB ALAM *Secretary* 9818946781

MANJEET KAUR *Secretary* 9210565722

RAHUL AGGARWAL *Cashier* 9871420213

सेवा में,
श्रीमान अनिल बैजल,IAS
माननीय उपराज्यपाल महोदय,
राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार दिल्ली,
6,राज निवास मार्ग,सिविल लाइन्स,
नई दिल्ली -110054

मुख्यमंत्री कार्यालय (सहायता कक्ष) 5 SEP दिल्ली सरकार

विषय: दिल्ली में 2260 राशन दुकानदार की मार्जिन मनी/कमीशन को निर्धारित समय सीमा में बढ़ाने के सन्दर्भ में सकारात्मक आदेश/ निर्देश पारित करने हेतु.

निवेदन यह है कि, दिल्ली के 2260 राशन दुकानदार दिल्ली के 73 लाख जरूरतमंद उपभोक्ताओं को प्रत्येक माह सस्ते राशन का वितरण करते है! परन्तु दिल्ली के 2260 राशन दुकानदार भारत सरकार, दिल्ली सरकार और खाद्य एवं संभरण विभाग-दिल्ली के बीच में फंस कर अपनी आजीविका को बचाने तथा अपने परिवार का भरण-पोषण करने हेतु लगातार भ्रष्टाचार/कालाबाजारी के दलदल में गिरते जा रहे है! कई वर्षो से दिल्ली सरकारी राशन डीलर्स संघ-दिल्ली प्रदेश (DSRDS - DELHI) लगातार भारत सरकार, दिल्ली सरकार और खाद्य एवं संभरण विभाग-दिल्ली को व्यक्तिगत तौर पर मिलकर, लिखित साक्ष्य देकर, धरना-प्रदर्शन करके व अन्य कई प्रकार से यह समझाने का प्रयत्न कर रहा है कि जब तक राशन दुकानदार को उसके परिवार के भरण-पोषण हेतु उचित मार्जिन-मनी/कमीशन नहीं मिल जाती, तब-तक खाद्य एवं संभरण विभाग-दिल्ली में फैले भ्रष्टाचार का अंत नही हो सकता है! आप जितनी मर्जी सख्ती कर ले, लगातार विजिट कर ले, नए-नए कानून बना ले अथवा आदेश पारित कर ले उससे केवल और केवल विभाग के भ्रष्ट अधिकारियो की जेब ही गर्म होगी! आम जनता को लाभ मात्र समुद्र में एक लौटे जितना होगा.

दिल्ली के राशन दुकानदारों की कमीशन बढ़ाने हेतु, दिल्ली सरकारी राशन डीलर्स संघ-दिल्ली प्रदेश(DSRDS - DELHI) के सदस्यों की जब भी विभागीय अधिकारियो से मुलाकात होती है, उनका केवल यही जवाब होता है कि आपकी कमीशन बढ़नी चाहिए हमने फाइल बना कर सरकार को भेज दी है, परन्तु उस फाइल के विषय में कोई कुछ भी नही जानता है! क्योंकि कुछ भ्रष्ट अधिकारी जानबूझकर अपने पद का दुरूपयोग करते हुए उस फाइल में अपनी रूचि नही दिखाते और उसे किसी कोने में फेंक देते है! इसका मुख्य उद्देश्य

SHIV KUMAR GARG
President
9212567435

JAGDISH PRASHAD
Sr. Vice President
9810406015

KUNJ BIHARI BANSAL
Vice-president
9810630323

SHYAM SUNDAR
Vice President
9911178848

SUNIL SHARMA
Vice President
9310023180

MANOJ SHARMA
Vice President
9582203929

HARI KRISHAN (LILU)
Vice-President
9212442834

SITA RAM
Gen. Secretary
9312238830

RAJNEESH SHARMA
Secretary
9818569678

SAURABH GUPTA
Secretary
9810943745

MATLOOB ALAM
Secretary
9818946781

MANJEET KAUR
Secretary
9210565722

RAHUL AGGARWAL
Cashier
9871420213

Ref. : DSRDS-DELHI/2017/NO. 212-215 Date : 31-08-17

यह है कि, राशन दुकानदारों का कमीशन बढ़ने पर ----------- राशन दुकानदार राशन की कालाबाजारी, नहीं करेंगे जिस वजह से दिल्ली के राशन उपभोक्ताओं को उनका पूरा राशन सही मूल्य पर मिलेगा और उन भ्रष्ट अधिकारियो को मिलने वाली लाखो-करोडो रुपये की काली-कमाई का जरिया ख़तम हो जाएगा! ऐसे अधिकारी आम जनता व सरकार के माननीय पदाधिकारियों को हमेशा अँधेरे में रखते हुए उन्हें मिथ्या जानकारिया उपलब्ध कराते है, ताकि राशन दुकानदार का जनता व सरकार से कोई समन्वय न बन पाए और विभागीय के भ्रष्ट अधिकारी राशन दुकानदार का लगातार शोषण करते रहे! जिसका खामियाजा अन्ततः आज भी दिल्ली की जरूरतमंद आम जनता भुगत रही है

गौरतलब हो कि, भारत का राजपत्र प्रकाशन दिनांक 20 मार्च 2015 (खाद्य और सार्वजानिक वितरण विभाग) के खंड 9 -उचित दर दुकानों का अनुज्ञप्तिकरण और विनियमन के उपखण्ड 7 के अनुसार यह निर्देश प्रकाशित किया गया है कि:-

" राज्य सरकार उचित दर दूकान के स्वामी के लिए मार्जिन की रकम नियत करेगी जिसका आवधिक रूप से उचित दर दुकान प्रचालको की ग्राह्य व्यवहार्यता का सुनिश्चित करने के लिए पुनर्विलोकन किया जाएगा ".

"The State Government shall fix an amount as the fair price shop owner's margin, which shall be periodically reviewed for ensuring sustained viability of the fair price shop operations."

इसका स्पष्ट रूप से अर्थ यह यह है कि, राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि, उचित दर दुकानदार को उपयुक्त मार्जिन मनी मिले, जिससे वह पूर्ण रूप से ईमानदारी के साथ अपना व अपने परिवार का भरण पोषण कर सके! परन्तु दिल्ली के राशन दुकानदारों का यह दुर्भाग्य है कि दिल्ली सरकार, भारत सरकार के उपरोक्त राजपत्र की अवहेलना कर

DELHI SARKARI RATION DEALER'S SANGH - DELHI
Office : Shop No. 2 & 3, C-4, DDA Market, First Floor, Lawrance Road, Keshavpuram, Delhi-110035
E-mail : dsrdsdelhi@gmail.com
Website : www.dsrdsdelhi.com
स्वच्छ भारत एक कदम स्वच्छता की ओर
DSRDS

SHIV KUMAR GARG
President
9212567435

JAGDISH PRASHAD
Sr. Vice President
9810406015

KUNJ BIHARI BANSAL
Vice-president
9810630323

SHYAM SUNDAR
Vice President
9911178848

SUNIL SHARMA
Vice President
9310023180

MANOJ SHARMA
Vice President
9582203929

HARI KRISHAN (LILU)
Vice-President
9212442834

SITA RAM
Gen. Secretary
9312238830

RAJNEESH SHARMA
Secretary
9818569678

SAURABH GUPTA
Secretary
9810943745

MATLOOB ALAM
Secretary
9818946781

MANJEET KAUR
Secretary
9210565722

RAHUL AGGARWAL
Cashier
9871420213

Ref. : DSRDS-DELHI/2017/NO. 212-215 *Date :* 31-08-17

रही है! दिल्ली जैसे महंगे राज्य में राशन दुकान चलाने हेतु अन्य राज्य की अपेक्षा अधिक धन/ कमीशन/मार्जिन-मनी की आवशयकता है.

दिल्ली सरकारी राशन डीलर्स संघ-दिल्ली प्रदेश (DSRDS - DELHI), दिल्ली के समस्त उचित दर दुकानदारों की तरफ से आपको हाथ जोड़कर यह निवेदन करता है, कि दिल्ली के सभी 2300 राशन दुकानदारों की मार्जिन मनी को बढ़ाने की कड़ी में अपना सहयोग देते हुए सम्बंधित विभागों को आदेश / निर्देश जारी करे कि, निर्धारित समय सीमा में कार्यवाही करते हुए बिना वजह उत्पन्न किए गए व्यवधानों को हटाकर मार्जिन मनी/कमीशन की फाइल पर सकारात्मक निर्णय लेकर आपको तथा DSRDS-DELHI को भी सूचित करे! ताकि दिल्ली के राशन दुकानदार, दिल्ली के 73 लाख राशन उपभोक्ताओं की ईमानदारी के साथ सेवा कर सके.

दिल्ली सरकारी राशन डीलर्स संघ-दिल्ली प्रदेश (DSRDS - DELHI) आशा करता है कि आपके द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना DSRDS-DELHI को अवश्य देंगे.

सधन्यवाद

31/8/17

शिव कुमार गर्ग
अध्यक्ष - दिल्ली सरकारी राशन डीलर्स
संघ-दिल्ली प्रदेश(DSRDS-DELHI)
MOB:- 9212567435, 8700370981

Delhi Sachivalaya I.P. Estate, New Delhi-02
RECEIVED
Govt. of NCT of Delhi
0 5 SEP 2017

प्रतिलिपि : (1) श्रीमान अरविन्द केजरीवाल, माननीय मुख्यमंत्री, राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
(2) श्रीमान इमरान हुसैन, माननीय खाद्य मंत्री, राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार दिल्ली
(3) डा. M.M. कुट्टी, IAS , मुख्य सचिव, राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार दिल्ली

संलग्न: (1) दिल्ली में राशन डीलर्स की मासिक आय का ब्यौरा एक तालिका के माध्यम से
(2) दिल्ली में राशन दुकान के मासिक खर्चो का विवरण एक तालिका के माध्यम से.
(3) भारत का राजपत्र प्रकाशन दिनांक 20 मार्च 2015 (खाद्य और सार्वजानिक वितरण विभाग) के खंड 9 -उचित दर दुकानों का अनुज्ञप्तिकरण और विनियमन के उपखण्ड 7 की प्रतिलिपि

DELHI SARKARI RATION DEALER'S SANGH - DELHI

Office : Shop No. 2 & 3, C-4, DDA Market, First Floor, Lawrance Road, Keshavpuram, Delhi-110035
E-mail : dsrdsdelhi@gmail.com
Website : www.dsrdsdelhi.com

DSRDS

SHIV KUMAR GARG
President
9212567435

JAGDISH PRASHAD
Sr. Vice President
9810406015

KUNJ BIHARI BANSAL
Vice-president
9810630323

SHYAM SUNDAR
Vice President
9911178848

SUNIL SHARMA
Vice President
9310023180

MANOJ SHARMA
Vice President
9582203929

HARI KRISHAN (LILU)
Vice-President
9212442834

SITA RAM
Gen. Secretary
9312238830

RAJNEESH SHARMA
Secretary
9818569678

SAURABH GUPTA
Secretary
9810943745

MATLOOB ALAM
Secretary
9818946781

MANJEET KAUR
Secretary
9210565722

RAHUL AGGARWAL
Cashier
9871420213

Ref. : DSRDS-DELHI/2017/NO. 212-215

Date : 31-08-17

दिल्ली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को भ्रष्टाचार मुक्त तथा सुचारू रूप से चलाने हेतु दिल्ली सरकारी राशन डीलर्स संघ-दिल्ली प्रदेश(DSRDS - DELHI) की मांग/ सुझाव निम्नलिखित है :-

1. दिल्ली में राशन डीलर्स की मासिक आमदनी को मासिक खर्चो से ज्यादा करने हेतु, दिल्ली के राशन डीलर्स की मार्जिन मनी/ कमीशन को अविलम्ब 70 पैसे प्रति किलो से बढ़ाकर 2.80 रुपये प्रति किलो करे सरकार.

2. दिल्ली के राशन डीलर्स की एक वर्ष,(01.09.2013 TO 31.08.2014) अवधि का बकाया (AREAR) मार्जिन मनी/ कमीशन को शीघ्र-अति-शीघ्र दिलवाने के निर्देश करे सरकार.

3. दिल्ली में सभी राशन डीलर्स के कोटे/ राशन की मात्रा को MCD वार्ड अनुसार बराबर (RATIONALIZATION) करे सरकार.

4. दिल्ली में राशन डीलर्स के लाइसेंस के नवीनीकरण हेतु लाइसेंसी की अधिकतम उम्र 60 वर्ष से पाबंदी हटाए सरकार.

5. दिल्ली में सभी राशन दुकानों के लाइसेंस के नवीनीकरण भविष्य में ऑनलाइन करे सरकार.

6. दिल्ली में राशन वितरण के उपरान्त होने वाली छिद्दत (HANDLING LOSS) को पहले की भांति स्वीकृति दे सरकार

7. दिल्ली में राशन की दूकान पर राशन उतरवाई (UNLODING) के बाद , लेबर द्वारा अनावश्यक चार्ज 10 रुपये प्रति क्विंटल की सख्ती से बंद करे सरकार.
→ वसूली को

31/8/17

DELHI SARKARI RATION DEALER'S SANGH-DELHI

DETAIL OF ZONAL WISE FPS (FAIR PRICE SHOP) ALOCATION OF WHEAT AND RICE

FOR THE MONTH OF SEPTEMBER-2017

S.NO.	ZONE NAME	FPS HAVING ALLOCATION BETWEEN 0-50 QUANTAL	FPS HAVING ALLOCATION BETWEEN 50-100 QUANTAL	FPS HAVING ALLOCATION BETWEEN 100-200 QUANTAL	FPS HAVING ALLOCATION BETWEEN 200-300 QUANTAL	FPS HAVING ALLOCATION BETWEEN 300-400 QUANTAL	FPS HAVING ALLOCATION ABOVE 400 QUANTAL	TOTAL NUMBER OF FPS's
1	WEST	19	50	118	84	2	0	273
2	NORTH WEST	10	25	141	126	23	2	327
3	NORTH EAST	2	58	177	81	23	2	343
4	NEW DELHI	20	35	38	25	3	1	122
5	SOUTH	15	49	139	80	2	0	285
6	SOUTH WEST	13	44	190	73	3	3	326
7	EAST	11	44	114	63	3	0	235
8	CENTRAL	9	23	71	43	8	3	157
9	NORTH	6	30	91	52	7	6	192
	TOTAL	**105**	**358**	**1079**	**627**	**74**	**17**	**2260**
A	PERCENTAGE OF ALLOCATION FOR FPS's	**4.65%**	**15.84%**	**47.74%**	**27.75%**	**3.27%**	**0.75%**	**100%**
B	MAXIMUM INCOME OF FAIR PRICE SHOP @70 Rs. P. QTL.	**3500/-**	**7000/-**	**14000/-**	**21000/-**	**28000/-**	**30000/-**	**MONTHLY INCOME EXLUDING ALL EXPENSES OF FPS**

*ABOVW MENTIONED DATA CONFIRMED FROM THE DEPARTMENTAL WEBSITE- http://nfs.delhi.gov.in/Citizen/FPSWiseAllocation.aspx?type=SEP==17

ABOVE DETAIL PREPARED BY MR. RAHUL AGGARWAL AND CHECKED BY MR. SHIV KUMAR GARG AS DATA FOUND ON THE WEBSITE OF FOOD & SUPPLIES DEPARTMENT,GONCT OF DELHI

DELHI SARKARI RASHAN DEALERS SANGH DELHI

DETAILS OF ESTIMATION COST OF RUNNING A FAIR PRICE SHOP IN DELHI

FOR " A" CATEGORY LOCATION

A	RENT OF THE FAIR PRICE SHOP(FPS) ----- SIZE 5M*3M*3M = 45QUBIC METER WHICH IS SITUATED ON 30 FEET WIDE ROAD AS PER DEPARTMENT NORMS (AVERAGE) Let the rental value be assessed & fixed, adopted accordingly, Area in Category – A (Anand Niketan, Basant Lok DDA Complex, Bhikaji Cama Place,Friends Colony, Kalindi Colony, Lodi Road Industrial Area, Nehru Place, New Friends Colony, Panchshila Park ,Rajendra Place, Shanti Niketan, Sunder Nagar, Vasant Vihar)	25,000/-
	ELECTRICITY CHARGES OF THE FPS----- As each FPS power is consumed for electronic weighing scale, exhaust fan, normal fan, tube light plus one bulb inside &one outside & now onwards it may be for the Sales Device/Machine as well--	2,000/-
C	LABOUR CHARGES --- LABOUR CHARGES OF AN UNSKILLED LABOUR AT FPS FOR FILLING/WEIGHING ETC-----[As per the latest minimum wages [illegible] 01st April [illegible] by the Labour Department of GONCT for an unskilled labour	13,350/-
D	STATIONARY CHARGES ------ Each FPS has to arrange stationary as per norms of the Department for cash memos/sales registers/ stocks register / Ration cards register (category wise) & carbons etc	1,000/-
	CHARGES TO BE MADE BY DSCSC LTD. AT THE TIME OF PAYMENT OF SFAs THROUGH ECS	102/-
F	LOSS OF INTEREST ON CAPITAL BLOCKED FOR ONE MONTH	500/-
	METROLOGY EXPENSES ON STAMPING FOR VERIFICATION CERTIFICATE(V.C.) & MAINTAINANCE EXPENCESS OF ELECTRONIC WEIGHING MACHINE/ WEIGHMENT CHARGES AT THE TIME OF RECEIPTS OF SFAs etc.	300/-
	SHORTAGE & HANDLING LOSS/ OPERATIONAL LOSS OF FOOD GRAINS AT THE TIME OF DELIVERY AND DISTRIBUTION OF FOOD GRAINS IN RETAIL BY FPS's IN DELHI.	1000/-
	EXPENSES ON MAINTENANCE OF BOOKS OF ACCOUNTS/FILING OF INCOME TAX RETURNS BY CHARTERED ACCOUNTANT etc.	250/-
	VARNER CHARGES/BAKSHISH UNOFFICIALLY DEMANDED/CHARGED BY LABOURERS OF TRANSPORT CONTRACTORS OF DSCSC LTD AT THE TIME OF UNLOADING OF SFAs IN THE PREMISES OF FPSs@ Rs10/- per quintal	1,000/-
K	HIDDEN CHARGES UNIVERSALLY KNOWN TO THE DEPARTMENT AT THE TIME OF RENEWAL OF AUTHORISATION OF FPS's, DUE TO NON-AVAILABILITY SERVICE OF THE RENEWAL ONLINE etc.	1,000/-
L	UNFORESEEN MISCELLANEOUS EXPENSES, PETROL, CONVEYANCE/MOBILE PHONE CHARGES,etc	3,000/-

TOTAL EXPENSES APPROXIMATELY [A TO L] Rs 48,502/- p.m.

(13) The State Government shall exercise necessary checks to ensure that full quantity and the same quality of foodgrains as lifted by them reaches their godowns and in turn at the fair price shop.

7. **Distribution of foodgrains by States.**—(1) The allocation of foodgrains made by the Central Government under the Targeted Public Distribution System to the State Government shall be used for distribution as per the provisions of the Food Security Act and not for any other purpose.
(2) The State Government shall furnish a utilisation certificate every year in the format as at Annex-IV.
(3) The State Government shall ensure, through the authorised agency, physical delivery of foodgrains to the fair price shop by [illegible] of the month preceding the allocation month and in any case not [illegible] the allocation [illegible]
(4) The State Government [illegible] confirming delivery of foodgrains [illegible] in order to distribute to eligible households during the allocation month.
(5) [illegible] fair price shop [illegible] or more persons as may be authorised by the State Government such as members of the local authority, Executive Officer/Secretary of the local authority, members from the vigilance committees [illegible]

8. **Licensing and Regulation of fair price shops.**—(1) The State Government shall issue an order under section 3 of the Act, but not inconsistent with this Order, for regulating the sale and distribution of the essential commodities.
(2) The licences to the fair price shop owners shall be issued under the said order and the order issued by the State Government shall be notified and displayed on web portal.
(3) The designated authority appointed by the State Government shall issue the licences to the fair price shop owners.
(4) The State Government shall accord preference to public institutions or public bodies such as panchayats, self help groups, co-operative societies in licensing of fair price shops and management of fair price shops by women or their collectives.
(5) The licences to the fair price shop owners shall be issued keeping in view the viability of the fair price shop.
(6) The State Government shall ensure that the number of ration card holders attached to a fair price shop are reasonable, the fair price shop is so located that the consumer or ration card holder does not have to face difficulty to reach the fair price shop and that proper coverage is ensured in hilly, desert, tribal and such other areas difficult to access.
(7) The State Government shall fix an amount as the fair price shop owner's margin, which shall be periodically reviewed for ensuring sustained viability of the fair price shop operations.
(8) The State Government shall put in place a mechanism to ensure the release of fair price shop owner's margin without any delay.
(9) The State Government may allow sale of commodities other than the foodgrains distributed under the Targeted Public Distribution System at the fair price shop to improve the viability of the fair price shop operations.

9. **Operation of fair price shops.**—(1) The fair price shop owner shall disburse foodgrains to the ration card holder as per his entitlement under the Targeted Public Distribution System.
(2) The ration card holder may draw his full entitlement of foodgrains in more than one instalment.
(3) The fair price shop owner shall not retain the ration cards after the supply of the foodgrains.
(4) The licence issued by the State Government to the fair price shop owner shall lay down the duties and responsibilities of the fair price shop owner which shall include, inter alia,—

(i) sale of foodgrains as per the entitlement of ration card holders under the Targeted Public Distribution System at the prescribed retail issue price;
(ii) display of information on a notice board at a prominent place in the shop on daily basis regarding (a) entitlement of foodgrains, (b) scale of issue, (c) retail issue prices, (d) timings of opening and closing of the fair price shop including lunch break, if any, (e) stock of foodgrains received during the month, (f) opening and closing stock of foodgrains, (g) the mechanism including authority for redressal of grievances with respect to quality and quantity of foodgrains under the Targeted Public Distribution System and (h) toll-free helpline number;
(iii) maintenance of the records of ration card holders, e.g. stock register, issue or sale register shall be in the form prescribed by the State Government including in the electronic format in a progressive manner;
(iv) display of samples of foodgrains being supplied through the fair price shop;

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
DEPARTMENT OF FOOD, SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS
K-BLOCK, VIKAS BHAWAN, I.P. ESTATE, NEW DELHI-110002
(DISTRIBUTION BRANCH)

No.F.15(11)/CFS(D)/2003/ [illegible] Dated: [illegible]

ORDER

The Lt. Governor, Delhi is pleased to revise the margin money of Fair Price Shop Dealers on the Specified Food Articles (SFAs) i.e. wheat and rice from the existing Rs.35/- per quintal to Rs.70/- per quintal.

The Government of India has enacted the National Food Security Act, 2013. The same has been implemented in the NCT of Delhi. Under the provisions of NFSA, 2013 there are two categories of ration card holders i.e. AAY Households and Priority Households. They are getting SFAs at highly subsidized rates i.e. wheat @ Rs.2/- per kg. and rice @ Rs.3/- per kg. The expenditure incurred on the payment of margin money for the SFAs issued to AAY and Priority Households(which includes the old BPL,JRC and RCRC ration card holders) will be borne by the Food, Supplies & Consumer Affairs Department, Govt. of NCT of Delhi under MH-3456-D.1(3)(1)- Streamlining of Public Distribution System with focus upon below poverty line. The revised rate of margin money payable to the FPS Dealers for these categories of households in NCT will be effective from 1st September, 2014.

Consequent upon revision of margin money, the retail price of Above Poverty Line (Stamped) (APL-S) category for wheat are revised from the existing Rs.7.05 per kg. to Rs.7.40 per kg. and for rice from the existing Rs.9.25 per kg. to Rs.9.60 per kg. to the consumers.The revised rates for this category will be effective from 01/12/14.

This issues with the concurrence of Finance (Expenditure-II) Department, Government of NCT of Delhi vide their CD No.000251475 dated 4.8.2014.

This issues with the prior approval of Secretary-cum-Commissioner, F&S.

17/11/14

(AJAY KUMAR GUPTA)
ADDL. COMMISSIONER, F&S

9. Effective date of Central assistance.—The Central assistance to the State Government shall be effective from the date of allocation of foodgrains under the Act and shall be only for allocations made for entitled persons and households.

10. Release of Central assistance.—(1) In the first year of the implementation of the Act, seventy five per cent. of the total Central share of expenditure, calculated on the basis of estimated annual allocation of food grains for the entitled persons and households, the norms of expenditure and Central share as mentioned in sub-rule (1) of rule 7 shall be released to the State Government in advance as first instalment, at the beginning of financial year.

(2) The balance twenty five per cent. of the Central assistance shall be released in the following financial year.

(3) The admissibility of total annual Central assistance and its amount shall be calculated out on the basis of,-

(a) the quantity of food grains actually distributed during the financial year under the Act;

(b) actual per quintal rates at which the expenditure was incurred by the State Government or Union territory on intra-State movement and handling of food grains and margins paid to fair price shop dealers, or the norms of expenditure specified in sub-rule (1) of rule (7), whichever is lower; and

(c) norms of Central share specified in sub-rule (1) of rule 7.

(4) After release of first instalment, if any amount is due, it shall be released as the second instalment.

(5) In case of release of excess amount in the first instalment, the same shall be adjusted against due Central assistance for the subsequent financial year.

(6) For release of second instalment, the State Government shall furnish information in the proformas prescribed at Schedule I and Schedule II to these rules.

(7) In subsequent years, Central assistance shall be calculated on the basis of;

(a) estimated annual allocation of food grains for the entitled persons and households to the State;

(b) the actual per quintal rates at which expenditure was incurred by the State Government or Union territory during the previous year on intra-State transportation and handling of food grains and margin paid to the fair shop dealers separately or the norms of expenditure mentioned in sub-rule (1) of rule 7 whichever is lower; and

(c) norms of Central share specified in sub-rule (1) of rule 7.

(8) Seventy five per cent. of the Central assistance estimated under sub-rule (7), shall be released as first instalment in the beginning of the financial year.

(9) The balance twenty five per cent. Central assistance shall be released as second instalment in the next financial year subject to the conditions specified in sub-rules (3) (4) (5) and (6).

11. Release of Central assistance for previous years.—In States and Union territories where implementation of the Act had started in the year(s) before coming into force of these rules, release of due Central assistance for previous years shall be made on the basis of information to be furnished by the States or Union territories, as the case may be, in the proformas prescribed at Schedule I and Schedule II to these rules.

12. Utilisation certificate.—The State Government and Union territory shall submit utilisation certificate in prescribed proforma to the Central Government, as provided under General Financial Rules, 2005.

[No. 15-34/2014-NFSA]

NILAMBUJ SHARAN, Economic Adviser